# RAJYA SABHA

*Monday, 23rd November 1987/2 Agrahayana, 1909 (Saka)*

The House met at leven of the clock, **Mr. Chairman** in the Chair.

## ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

### Increase in Demand for Diesel and Crude Oil

*221 SHRI KAILASH PATI MISHRA:†

SHRI ASHWANI KUMAR:

Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) the estimated extent of increase in the demand for diesel in the country due to drought;

(b) what steps are being taken by Government to meet this demand in the far flung rural areas of the country; and

(c) how much more crude/diesel would have to be imported to meet this excess demand and at what estimated cost?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI BRAHM DUTT): (a) to (c) A statement is laid on the Table of the Sabha.

### Statement

(a) The increase in demand of diesel (HSD) during 1987-88, as estimated earlier for the year and as estimated now, is to the extent of 1,51,000 tonnes. This increase is mainly attributed to drought conditions;

(b) HSD is a free sale product and the oil marketing companies have instructions to meet its demand in full as far as possible through the expanding network of retail outlets. However, for meeting the increased demand of HSD in the drought-affected areas of the country and particularly in the North-Western region, Govt. and the Oil Industry have taken various measures such as close monitoring of supplies of HSD in the drought-affected areas, maintenance of close coordination with the Railways to maximise movement of petroleum products, building up of adequate stocks, etc.

(c) In order to meet the growing demand for various petroleum products, additional crude imports for processing in the refineries in the current year 1987-88 is likely to be 1.00 million tonnes at an estimated cost of Rs. 170 crores. As regards HSD, in view of increased indigenous production from the refineries, no additional import is proposed in the current year.

---

**श्री कैलाशपति मिश्र :** सभापति जी, सूखे की परिस्थिति का आकलन लगाने के लिये सैन्ट्रल टीम लगभग सभी राज्यों में गई है मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि जहां सूखा पड़ा है, अलग-अलग राज्यों से अतिरिक्त डीजल की मांग कितना है?

**श्री ब्रह्म दत्त :** जो राज्य और यूनियन टेरिटरी सूखे से प्रभावित हैं उनकी अलग-अलग मांग मैं निवेदन कर देता हूं कि दिल्ली, हरियाणा, वेस्ट यू० पी०, जम्मू और काश्मीर, पंजाब और राजस्थान की मांग अलग-अलग है और पूरे प्रदेशों की मांग अलग-अलग है। लेकिन उनकी मांग हम पूरे तौर से पूरी कर रहे हैं। यह मैं इस सदन को बता देना चाहता हूं कि दिल्ली की मांग अगस्त में 19 प्रतिशत ज्यादा थी, हरियाणा की 24 प्रतिशत, वेस्टर्न यू० पी० की 35 प्रतिशत, जम्मू और काश्मीर की 20 प्रतिशत, पंजाब के 44 प्रतिशत और राजस्थान की 29 प्रतिशत ज्यादा थी। इसे तथा तथा नार्थ वेस्ट के पूरे राज्यों की 31.45 प्रतिशत की ज्यादा मांग हमने पूरी की है और जितनी मांग है [illegible]

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Kailash Pati Mishra.

**श्री कैलाशपति मिश्र** : सभापति महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल नही मिल रहा है । जहा तक मुझे जानकारी है हर एक राज्य ने अपनी मांगों का मेमोरेंडम केन्द्रीय सरकार के पास भेजा है । अभी भी सूखे का प्रभाव है और वह अभी समाप्त नहीं हुआ है । मंत्री महोदय ने कहा कि आपूर्ति हो रही है । अभी मामले का अन्त नही हुआ है यह जो सूखे का असर है यह लगातार अगले बरसात तक चलने वाला है । मैं मंत्री महोदय से फिर से आग्रह करना चाहता हूं कि आप इसको टालिये मत । मैं जानना चाहता हूं कि अलग-अलग राज्यों ने पूरे 1987–88 वर्ष के लिये कितनी माग रखी है ? जरा इस मांग के आंकड़े बतलाइये और इसके साथ ही यह भी बताइये कि इस मांग की पूर्ति करने के लिये आपने क्या प्रबंध किये है ?

**श्री ब्रह्म दत्त** : मान्यवर, यह जो डीजल का प्रोडक्ट है इसकी अलग-अलग राज्यो से माग नही आती है, न कोई अलग से रिक्वैस्ट आती है और न आयी है। यह हमारी जिम्मेदारी है और हम खुद वितरण करते हैं, उसका उत्पादन करते हैं और उसकी रिफाइनिग करते हैं । माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि भगवान न करे कि दिसम्बर-जनवरी और जुलाई तक इसका असर हो । उनकी मांग पूरी की जायेगी और उसके लिये पूरे प्रबंध किये गये है ।

**श्री कैलाशपति मिश्र** : सभापति महोदय, लगता यह है कि सरकार बिल्कुल क्वालिटिक सिचुएशन क्रियेट करने पर तुली हुई है । मन्त्री महोदय ने जवाब दे दिया कि अलग-अलग माग नहीं आई है । केंद्रीय एक्सपर्ट टीम टूर करने के लिये सभी राज्यो में गई है और हर राज्य में उन्होंने बैठकर राज्य सरकारो से वार्ता की है और सब ने अपनी आवश्यकता वहा पर दिखाई है । यहां पर मंत्री महोदय केवल एक ही उत्तर दे रहे है कि हम सब मांगों की पूर्ति करेंगे । मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी तो होगी कि कठिनाइया कहा-कहा पर खडी होती है । जहा-जहा पेट्रोल पम्प और डीजल पम्प पहले से बने हुये है, अभी तक जो मेरी जानकारी है आपूर्ति करने की कोशिश वही तक है । फिर उनकी अपनी क्षमता भी सीमित रहती है । इसके साथ ही जहा पेट्रोल पम्प और डीजल पम्प नहीं बने हुये है वहा सरकार ने डीजल पहुंचाने के लिये कौन से प्रबध किये है ? इसके साथ ही मैं एक और यह प्रश्न पूछना चाहता हू कि जो सूखे और अकाल की परिस्थितिया है इससे किसान सबसे अधिक इस समय प्रभावित है । क्या आप डीजल की आपूर्ति सबसिडाइज्ड रेट पर करने के लिये तैयार है ? दोनों प्रश्नो का माननीय मन्त्री जी स्पष्ट उत्तर देने की कृपा करें ।

**श्री ब्रह्म दत्त** : मान्यवर, मैं यह आश्वासन नही दे सकता कि डीजल सबसिडाइज्ड रेट पर दिया जाएगा लेकिन मैं इतना आश्वासन जरूर दे सकता हूं कि डीजल का भाव नहीं बढ़ाया जाएगा ।

**श्री जशवंत सिंह** : कब तक नही बढ़ायेंगे ?

**श्री ब्रह्म दत्त** : जब तक यह संकट का समय रहेगा **(व्यवधान)** मैं भविष्य ये लिये कमिट नही कर सकता । लेकिन इस संकट के समय मे हमारे सामने ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नही है । माननीय सदस्य के दूसरे सवाल के विषय मे मुझे यह कहना है कि अलग-अलग स्टेट्स के लिये कोई एलोकेशन नही होता सिर्फ हम यह करते है कि प्रत्येक जगह की आवश्यकता की पूर्ति की जाए और जो हमारे वितरण प्वाइंट्स हैं उनके द्वारा पूरी डीजल की आपूर्ति हो रही है और मुझे इस बात का अनुभव हुआ है कि कोई शिकायत किसी भी राज्य से हमें नही मिली कि डीजल की सप्लाई की कमी है ।

**श्री अश्विनी कुमार** : माननीय सभापति महोदय, इस वर्ष सुखाड के कारण विशेष परिस्थिति उत्पन्न हुई है परन्तु मन्त्री महोदय का मैं ध्यान इधर आकर्षित करना चाहता हू कि आज तक

एग्रीकल्चर सेक्टर के अन्दर जो टोटल बिजली और पावर दी जा रही है वह अत्यन्त अल्प है। मेरे हिसाब से मेरी जानकारी है 1984-85 में टोटल पावर का केवल 12.70 एग्रीकल्चर सैक्टर को दिया जा रहा है और यह 1989-90 में घट करके 110 हो जाएगा। इसी प्रकार से टोटल आयल कन्जम्पशन का 10% एग्रीकल्चर सेक्टर में जा रहा है और यह भी 1989-90 में घट कर 9.60% आ जाएगा। आज जो विशेष परिस्थिति खेती के अन्दर बाढ़ और सुखाड़ के कारण पैदा हो गई है इसके लिये आपने यह आश्वासन भी दिया है कि हम सब जगह डीजल की आपूर्ति करेंगे और डीजल के दाम भी नहीं बढ़ायेंगे। आपने यह नहीं बताया कि कब तक आप दाम नहीं बढ़ायेंगे। यह जो आज विशेष परिस्थिति बाढ़ और सुखाड़ के कारण है जिसके कारण हमारा किसान अभी भी इन्द्र भगवान की ओर देखता रहता है मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आप ऐसी कोई योजना बना कर बिजली और पावर अधिक दे कर पैट्रोलियम प्रोडक्ट्स की सप्लाई बढ़ा कर किसानों को प्रोत्साहित करेंगे ताकि हमारे किसान अधिक से अधिक डीजल इंजिन लगायेंगे और देश में खेती का उत्पादन बढ़ सके?

**श्री ब्रह्म दत्त** मान्यवर, जहां तक विद्युत उत्पादन का सवाल है वह तो हमारे वरिष्ठ सहयोगी श्री साठे जी इन्तजाम कर रहे है। डीजल के बारे मे मैं कह सकता हूं कि कोई कमी नहीं होने दी जायेगी। अगर उद्योग के क्षेत्र में या ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और डीजल का अनुपात बढ़ना है तो उससे कोई अन्तर नहीं पड़ता लेकिन मुख्य बात यह है कि कृषि के क्षेत्र की मांग पूरी की जाए इसके लिए हम आयल रिफाइनरीज की क्षमता का पूरा उपयोग करेंगे. जहां-जहां स्टाक प्वाइंट्स हैं और रेलवे से कोआर्डिनेट करने का पूरा प्रबन्ध किया है। लेकिन इस प्रकार की शिकायत हम को अभी तक किसी भी स्टेट से नहीं मिली है कि वहां डीजल की कमी है।

**श्री शान्त त्यागी** मान्यवर, माननीय मन्त्री जी का देहाती क्षेत्रों से बहुत लगाव रहा है। देहात के लोगों को डीजल के लिए शहरों में दौड़ना पड़ता है। कई बार तो 20-30 लीटर डीजल के लिए आना पड़ता है। मैं मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या ग्रामीण क्षेत्रों में डीजल के अधिक पम्पिंग स्टेशन खुलवाने की तुरंत व्यवस्था करेंगे!

**श्री ब्रह्म दत्त** : मान्यवर, आवश्यकता के अनुसार हमारा हर साल का मार्किटिंग प्लान बनता है और इसमें हम इस बात पर ध्यान अवश्य देते है कि लोगों को इसके लिए अधिक दूर न जाना पड़े। मार्किटिंग प्लान में कुछ नये स्टेशन हर साल खोल लेकिन मुख्य बात फिर वही आती है कि आवश्यकता पूरी हो रही है और उसके विषय में कोई शिकायत नहीं है।

SHRI NAGEN SAIKIA: Sir, may I know from the Minister whether the Government is taking any steps to produce more crude than the scheduled target for the yearto meet the exrta demand?

SHRI BRAHM DUTT: Sir, we are already taking steps in this direction. As I said in this very august House several times, we are trying to locate more oil, we are trying to develop our oil fields by early production, repairing sick wills and also, if necessary, maintaining proper import by long-term contracts.

**श्री शरद यादव** सभापति महोदय, दुनिया के बाजार में तेलों के जो दाम है वे घटे है, गिर रहे हैं। जब-जब दुनिया के बाजार में तेलों के दाम बढ़ते है, क्रूड आयल के दाम बढ़ते है तब तब आपने इस देश में दाम लगातार बढ़ाने का काम किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब दुनिया के बाजारों में क्रूड आयल के दाम लगातार घट रहे हैं तो क्या इस देश में पहली बार आप एक अच्छा उदाहरण देंगे कि जो जाम घट रहे हैं उसके अनुसार या

उसके अनुपात मे घटाने का काम करेंगे । यदि उन दामों को नहीं घटाते हैं तो उतने ही दाम पर किसानो को डीजल सप्लाई करने का काम करेंगे ?

**श्री ब्रह्म दत्त** : दाम जरूर घटे थे पिछले वर्ष कुछ समय के लिए लेकिन अब 18 डालर प्रति बैरल पर स्टेब्लाइज्ड हैं । जो बाहर से हम लोगों को क्रूड आपूर्ति होती है वह लांग टर्मज कंट्रेक्ट पर होती है । हमारा प्रयास है कि हम दाम बढने न दें अब रिट्रोस्पे-ज क्टिवली घटाने में तो ज्यादा दिक्कत पड़ेगी ।

**श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी** : सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने कहा कि सूखे के कारण 1 लाख 51 हजार टन की मांग बतायी गयी है । मंत्री महोदय ने यह भी कहा कि इस साल कोई बाहर से डीजल वगैरह इम्पोर्ट नही किया जायेगा और इनको इंडिजेनस प्रोडक्शन से पूरा किया जायेगा । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि देश में कितनी रिफाइनरीज हैं जहां पर क्रूड आयल वगैरह का उत्पादन होता है और इनकी आपूर्ति करने के लिए खासकर किसानों को डीजल आयल वगैरह पहुंचाने के लिए, जहां सुखा और बाढ़ है, सरकार क्या तजवीज कर रही है तथा जहां रिफाइनरीज हैं वहां क्रूड आयल वगैरह में अभिवृद्धि करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

**श्री ब्रह्म दत्त** : हमारे पास रिफाइनिंग की कुल क्षमता करीब 48 मिलियन टन है जो हमारी आवश्यकता के मुताबिक है और इसमें हमारा जो अपना क्रूड प्रोडक्शन है वह 30 मिलियन टन के आसपास है, बाकी के लिए क्रूड आयल मंगाने का हम बंदोबस्त करते हैं । जैसा मैंने पहले निवेदन किया कि लांग टर्म कंट्रेक्ट के जरिए कुछ स्पाट बांइग के जरिए । हाई स्पीड डीजल आयल हम स्वयं हम स्वयं बनाते हैं और कुछ आयल प्रोडक्ट्स हम इम्पोर्ट करते हैं लेकिन आगे बढ़ती हुई आवश्यकता को देखते हुए हम नयी रिफाइनरीज करनाल और मंगलौर मे लगाने की कोशिश कर रहे हैं आसाम के बारे में भी विचार कर रहे है। यह पूरा विचार हमारे सामने है । हमारी रिफाइनिंग कैपेसिटी पूरी होनी चाहिए क्योंकि व्यवहारिक रूप से क्रूड आयल इम्पोर्ट करना आसान है और आयल प्रोडक्ट्स को इम्पोर्ट करना फिर उसको देश के विभिन्न भागो मे भेजना बडा मुश्किल पडता है । इसलिए हम उचित बंदोबस्त कर रहे है ।

SHRI BIR BHADRA PRATAP SINGH. Mr. Chairman, Sir, scarcity of electricity, high prices of electrcity and drought, all these have necessitated the increase in the import but increase in import day-by-day is equally dangerous to our national economy. Although the prices of diesel and petrol are not at great variance, we have subsidised for certain reasons. Now, they have started manufacturing diesel cars and diesel engines. I would like to know what policy you are going to adopt to curb the use of subsidised diesel for non-essential goods, for non-essential uses and by what time you propose to bridge the gap between the imported diesel oil and home-produced diesel oil.

SHRI BRAHM DUTT: Sir, there is no additional import of diesel oil. Import of crude is there, of course. We are taking all measures in exploring oil resources and inviting the reputed international companies to explore oil where we can join them in exploiting the same and also by adopting early production system in the new wells and by repairing sick wells. This demand is increasing and self-sufficiency can only depend on new oil finds which is a matter of luck. We can try for it but we are maintaining a balance between the imported one and the indigenous one, that is, more production indigenously and more import economically by long term contracts and we are also taking up conservation methods so

that more efficient engines are produced in this country and used in this country. Oil can be saved by that also. All these things are taken care of.

SHRI BIR BHADRA PRATAP SINGH: What about the non-essential uses for diesel cars or other things which are not essential?

SHRI BRAHM DUTT: We are taking care of that. Priority is given to essential use.

SHRI M. KADHARSHA: The last sentence of the Statement reads, "As regards HSD, in view of increased indigenous production from the refineries, no additional import is proposed in the current year." But the fact remains that crude production has become stagnant. Will the hon. Minister please state what the total production in the past three years was? Sir, the consumption of petroleum products has been growing at the rate of seven per cent and if you have to achieve the five per cent economic growth as envisaged by the Seventh Plan, crude production has to be increased. I would like to know from the hon. Minister what steps have been taken by the Government to increase the output of crude, off-shore and on-shore.

SHRI BRAHM DUTT: Crude production in 1985-86 was 30 168 million tonnes; in 1986-87 30.481 million tonnes; and in 1987-88 we have set a target of 30.464 million tonnes

SHRI M. KADHARSHA: Then where is the increase? It remains stagnant.

SHRI BRAHM DUTT: I am not saying it has increased. We are maintaining it at the optimum level. That is what we can do We cannot manufacture oil. That is our difficulty. We have to find it We have taken carious measures like, exploration, early production and repair of the sick wells. Oil cannot be manufactured in a factory We are maintaining the level and we are also trying to take advantage of the world market by long-term contracts with friendly countries and spot- buying when the rates are low.

ठाकुर सुरेन्द्र सिंह : सम्माननीय सभापति महोदय, व्यवहार मे यह देखने में आता है कि सरकार जिनको डीजल पम्प या पेट्रोल पम्प की डीलरशिप देती है, उनका व्यवहार बहुत ही आपत्तिजनक पाया गया है । ऐसा लगता है कि सरकार ने उनको डीजल बेचने का लाइसेंस नही, बल्कि गरीब और अनपढ़ किसानों को गाली बकने का लाइसेंस दे दिया हो ।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जिनको डीलरशिप एलाट की जाती है, उनके लिए कोई आचार-संहिता भी तैयार की गई है, और अगर की गई है, तो क्या उसके खिलाफ अगर कोई डीलर दुर्व्यवहार करता है, तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाती है ?

दूसरा, मैं जानना चाहता हूं कि अगर किसी क्षेत्र विशेष की मांग डीजल पम्प या पेट्रोल पम्प के खोलने के लिए उठाई जाती है आपके क्षेत्रीय कार्यालयों में, तो कोई कार्यवाही होती नहीं हैं, मैं देख रहा हूं, लेकिन क्या आपकी तरफ से कोई ऐसी एजेंसियां हैं, जो रीएक्ट करती है और सर्वे करवा कर वहां तुरन्त डीजल या पेट्रोल पम्प खोलने की कोशिश करती हैं ?

श्री ब्रह्म दत्त : माननीय, आचार-संहिता तो है ही कि सही रेट पर और सही दाम पर और सही मात्रा में डीजल दिया जाए, उसमें मिलावट न हो और इसको एन फोस करने के लिए हम लोगों की अपनी एजेंसिया भी है और एक्शन भी हम लेते हैं ।

जहां तक नई डिमांड आती है माननीय सदस्यों और दूसरे जन-प्रतिनिधियों

से डिमाड आती है, मेरे पास स्वय भी आती है हम उसका सर्वे करवाते हैं, लेकिन हर साल का एक मार्केटिंग प्लान बनता है और उसमें प्राथमिकता के आधार पर हम वह शामिल करते है।

जहां तक डीलरशपि देने का सवाल है, उसके लिए आयल सिलेक्शन बोर्ड बना दिये गये है, चार आयल सिलेक्शन बोर्ड है। उसमे एक रिटायर्ड जज है, एक रिटायर्ड आफिसर है। वह उसको देखते है और फिर अलाट करते हैं, लेकिन मार्केटिंग प्लान हम व्यावहारिक रूप से बनाते हैं, जितना हम दे सकें।

**श्री शरद यादव** : मान्यवर, उन्होंने सवाल क्या पूछा था और यह जवाब क्या दे रहे है। इन्होने पूछा था कि जो वह दुर्व्यवहार करते है—उसका आप क्या जवाब दे रहे है।

**श्री ब्रह्म दत्त** : वही जवाब है।

**श्री हरवेन्द्र सिंह हंसपाल** : मैं मंत्री महोदय को बधाई देता हू कि यह इन्होंने सही कहा कि डीजल की जितनी जरूरत पड़ी सूखे के दौरान, वह दिया गया। किसी कारण पंजाब मे बावजूद सूखे के इस साल 35 लाख टन से ज्यादा पैडी उन्होने सेंट्रल पूल में दी।

**श्री शान्ति त्यागी** : हमारे उत्तर प्रदेश ने भी...

**श्री हरवेन्द्र सिंह हंसपाल** : माननीय मंत्री जी ने अपने एक बयान मे सप्लीमेंट्री के जवाब मे शुरू में कहा था कि पंजाब ने 44 प्रतिशत अधिक डीजल इस साल इस्तेमाल किया।

तो मैं जानना चाहता हूं कि रुपयों के हिसाब से वह कितने करोड़ का अधिक डीजल पंजाब ने इस्तेमाल किया और आने वाली फसल में अगर जरूरत हुई, तो माननीय मंत्री जी यह आश्वासन दे कि दुबारा किसी तरह की दिक्कत, जैसे पहले नही आई, ऐसी नही आने देंगे।

**श्री ब्रह्म दत्त** : मान्यवर, यह तो मैं आश्वासन दे सकता हूं कि दिक्कत नही आने देंगे और जहां तक रुपये का सवाल है मेरा अनुमान है कि 50 करोड रुपये के करीब उन्होंने ज्यादा डीजल खरीदा है, लेकिन मैं इसकी जिम्मेदारी नही लेता हू कि यह पूरा ठीक है, मैं तो अन्दाजन कह रहा हूं चूंकि मैंने हिसाब नहीं लगाया है।

**श्री हरवेन्द्र सिंह हंसपाल** : मुझे आप सही-सही भिजवा दीजिएगा ?

**श्री ब्रह्म दत्त** : हा, मैं भिजवा दूगा। लेकिन मैं पंजाब के किसानो को बधाई देना चाहता हू कि उसके बावजूद उन्होंने प्रोडक्शन भी मेनटेन रखा था और हम लोगों ने उनकी डीजल की आपूर्ति भी सुनिश्चित की है।

**Effect of power shortage on cement production**

*222. SHRI D. B. CHANDRE GOWDA:

SHRI HARVENDRA SINGH HANSPAL:†

Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether the cement production in the country has been adversely affected due to power shortage during the current financial year;

(b) if so, what are the details in this regard;

(c) whether Government have taken any steps to provide adequate power to the Cement manufacturing units in the country to boost its production; and

(d) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI M.

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Harvendra Singh Hanspal.